अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

अखिल भारतीय साधारण सभा

आश्विन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2078, 18 अक्टूबर, दिल्ली

प्रस्ताव क्रमांक 1

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए सामूहिक प्रयास और समुचित संसाधन आवश्यक

सक्षम, दक्ष, ज्ञानवान, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से पूर्ण भारत के निर्माण की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक अभूतपूर्व शैक्षिक योजना प्रस्तुत करती है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की साधारण सभा का यह सर्वसम्मत मत है कि यह भारत की शिक्षा नीति में 34 साल बाद किया हुआ एक सामान्य परिवर्तन मात्र न होकर 1835 में लाए गए 'इंग्लिश एजुकेशन एक्ट' के 185 वर्ष बाद औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कर समर्थ और स्वाभिमानी भारत बनाने का गौरवशाली दस्तावेज है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की साधारण सभा संतोष व्यक्त करती है कि हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ शिक्षा नीति के संबंध में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रयास हूए हैं, जिससे शैक्षिक समुदाय में एक सामूहिक चेतना जागृत हुई है। पिछले वर्ष लाई गई इस नीति को व्यवहारिक धरातल पर लागू करने के लिए सरकार कई पहलों के साथ आगे बढ़ी है। समग्र शिक्षा अभियान को शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप नया रूप दिया गया है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्त करने के लिए स्पष्ट समयबद्ध रोडमैप SARTHAQ लाया गया है। NIPUN Bharat, NISHTHA 2.0, SAFAL, NETF, विद्या प्रवेश, बस्ता नीति, भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल एंट्री व एग्जिट, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम, भारतीय साइन लैंग्वेज का मानकीकरण, एनसीसी का वैकल्पिक विषय के रूप में चयन, उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की गाइडलाइंस, लर्निंग आउटकम आधारित आइटम बैंक, कला समन्वित शिक्षा, मनोदर्पण, DIKSHA, PARAKH, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, ब्लेंडेड लर्निंग आदि प्रमुख कदम दूरगामी प्रभाव लाने वाले हैं तथा शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शासन की प्रतिबद्धता और गंभीरता को रेखांकित करते हैं।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की साधारण सभा सरकार के प्रयासों का स्वागत करते हुए परिवर्तन की कुछ प्रक्रियाओं और धरातल की कुछ समस्याओं के प्रति अपनी गंभीर चिंता प्रकट करती है। शिक्षा तंत्र में किए गए उपर्युक्त और आगे आने वाले प्रस्तावित परिवर्तनों को एक समान रूप से नीचे तक लागू करने में कई गंभीर चुनौतियाँ हैं। देशभर में शिक्षकों की भारी कमी है, पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक लाखों पद खाली पड़े हैं। बिना प्रशिक्षकों के विभिन्न व्यावसायिक विषय संबंधी अपेक्षित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना संभव नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तंत्र में परिवर्तन करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है लेकिन बजट में इसके लिए किसी अलग फंड की घोषणा नहीं की गई है। शिक्षा पर खर्च के लिए प्रस्तावित सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक जाने के संबंध में कोई सकारात्मक शासकीय प्रयास अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। महासंघ का मानना है कि पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ा अवरोध है।

कोरोना महामारी की परिस्थितियों ने ऑनलाइन या ब्लेंडेंड शिक्षा को शिक्षा तंत्र में लाना पड़ा लेकिन डिजिटल डिवाइड और देश में डिजिटल आधारभूत संरचना की भौगोलिक विषमता सबके सामने ला दी है। शिक्षा नीति की अनुशंसाओं के अनुसार किसी भी तरह के तकनीकी नवाचार को नीचे तक ले जाने के लिए व्यापक स्तर पर आधारभूत संरचना खड़ी करनी होगी जिसके लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों का निवेश आवश्यक है। महासंघ की साधारण सभा का यह भी सुविचारित मत है कि तकनीक के अपने फायदों के साथ सीमा बंधन भी है, विशेष रूप से शिक्षण और अधिगम में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सीखने का मूल आधार प्रेक्षण करने, सुनने, प्रश्न पूछने, प्रयोग करने आदि में है। यह सभी व्यावहारिक अनुभव हैं जिनके लिए रुचि, प्रेरणा, जुड़ाव और यह समझने की आवश्यकता होती है कि वह क्यों सीख रहे हैं। शिक्षा में तकनीक का एकीकरण इसे दृष्टिगत रखते हुए ही किया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह साधारण सभा यह समझती है कि कोरोना महामारी के चलते विपरीत प्रवास, नौकरियों का छूटना, आर्थिक मंदी और ऑनलाइन पढ़ाई की मजबूरी शिक्षा के लिए बहुत हानिकारक रहे हैं। ड्रॉपआउट दर में काफी वृद्धि हुई है तथा अधिगम अंतराल भी बहुत अधिक बढ़े हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तंत्र में परिवर्तनों को नीचे तक उतारने से पहले इन अंतरालों को पाटने

के लिए सामूहिक प्रयासों की महती आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समग्र और सफल क्रियान्वयन राज्य और केंद्र सरकारों के मिले-जुले प्रयास से ही संभव हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने इस दिशा में अच्छी प्रगति की है लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में इस विषय को लेकर उदासीनता की स्थिति बनी हुई है।

शिक्षा नीति को पूरी तरह जमीन पर उतारने के लिए अपने-अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर सभी पक्षों को देश के भविष्य के लिए एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। महासंघ का यह मानना है कि शिक्षकों, विद्यार्थियों और सभी हितधारकों को तंत्र में होने वाले परिवर्तनों के बारे में सकारात्मक मानसिकता के साथ स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। एतदर्थ यह साधारण सभा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, सामाजिक संस्थाओं, विशेषज्ञों, अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों को अपने-अपने स्तर पर एकमुखी होकर काम करने तथा शैक्षिक संस्थानों, कार्यान्वयन एजेंसियों, विद्यार्थियों और औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख लोगों के बीच एक सहजीवी संबंध स्थापित करने का आह्वान करती है ।

❑❑❑

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

अखिल भारतीय साधारण सभा

आश्विन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2078, 18 अक्टूबर, दिल्ली

प्रस्ताव क्रमांक-2

स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का पर्व बनें

स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम सब के लिए पवित्र अवसर है कि उन सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं का स्मरण करें जिन्हें आजादी की लड़ाई लड़ते समय हमारे पूर्वजों ने संजोया था। किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वह अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को सिखाता है, उन्हें संस्कारित करता है और उन्हें निरंतर प्रेरित करता है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम लंबे संघर्ष, असंख्य बलिदानों और तपस्याओं की पावन गाथा है, जिसकी परिणति 74 साल पहले स्वाधीन भारत के रूप में हुई। यह महोत्सव 'हम भारत के लोगों' के सामूहिक सपनों को मूर्त रूप देने और अपने गौरवशाली इतिहास के आधार पर अपने सांस्कृतिक जीवन को सुरक्षित रखते हुए भारत के पुनर्निर्माण की तैयारी का उद्घोष है।

भारत की युवा पीढ़ी दुनिया में आज सबसे बड़ी है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की साधारण सभा का यह सुविचारित मत है कि अपनी जड़ों का गौरव बोध लिए नई सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम, दुनिया को नेतृत्व देने वाला चिर पुरातन-नित्य नूतन भारत हम अपनी इसी देह और इन्हीं आँखों से देख सकें इसके लिए स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भारत के जन-जन का और हर मन का पर्व बनना चाहिए।

स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव आजादी के संघर्षों की पवित्र ऊर्जा के आलोक में जनभागीदारी के साथ नवोन्मेषी कार्यक्रमों की रचना का सुअवसर है। संपूर्ण देश में छोटे-छोटे स्थानिक कार्यक्रम एक बड़े राष्ट्रीय हित को साध सकते हैं।

महासंघ का मानना है कि स्वतंत्रता आंदोलन की कई घटनाएँ और स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान देश के सामने या तो आया नहीं या जिस रूप में आना था उस रूप में नहीं आ पाया। यह साधारण सभा सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों और समाजजन से इस बारे में विश्वस्त जानकारी देश के समक्ष लाने का आह्वान करती है ताकि इन गुमनाम या अल्प प्रकाशित संघर्षों से हम सब प्रेरणा पा सकें जिन्होंने देश के हर भू-भाग में और हर कालखंड में स्वतंत्रता की मशाल को जलाए रखा।

स्वतंत्रता की ज्योति को देशभर में जलाए रखने का अपने ढंग से हमारे संतों, आचार्यों और शिक्षकों ने भी किया। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत के राष्ट्रीय आदर्शों और आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा के माध्यम से स्व का जागरण करने वाले प्रयासों की एक लंबी शृंखला रही है। देश के महापुरुषों ने भारत के लिए कैसी शिक्षा पद्धति का सपना देखा और जिया था, इस पर विमर्श और विचार करने का भी यह एक पवित्र अवसर हमें मिला है।

आजादी के आंदोलन के इतिहास की तरह ही आजादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा हम भारतीयों के समर्पण, उद्यम और प्रतिभा का साक्षी रही है। ज्ञान-विज्ञान से लेकर सामाजिक, आर्थिक हर क्षेत्र में भारत की प्रगति और उपलब्धि को फिर से जानने और इस अवधि में रही कमियों पर लज्जित होने के स्थान पर दूर करने का संकल्प लेने का एक स्वर्णिम समय यह महोत्सव बने, ऐसा महासंघ की साधारण सभा का सर्व सम्मत मत है।

महासंघ अपने सदस्यों सहित समस्त शिक्षक समुदाय से इस अमृत वेला में यह आह्वान करता है कि वे अपने अपने स्थान पर समाज को दिशा देने वाले और प्रेरणादायी कार्यक्रमों की रचना करें। 'मेरा शिक्षा संस्थान-मेरा तीर्थ'; विद्यार्थियों में देश प्रेम, अपनी चेतन्य सांस्कृतिक विरासत के प्रति गौरव बोध, और भारत की एकता को पुष्ट करने वाली गतिविधियाँ; भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, उसके बाद की यात्रा और हमारा दायित्व जैसे विषयों पर संगोष्ठियाँ और व्याख्यान; स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के लिए जागरण अभियान आदि नवोन्मेषी कार्यक्रमों के माध्यम से हमसे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति इस अमृत महोत्सव का हिस्सा बने और हमारे व्यक्तिगत-सामूहिक प्रयास भारत को परम वैभव की ओर ले जाने में सक्षम हो, यह महासंघ की अपेक्षा है।

महासंघ की यह साधारण सभा विश्वास व्यक्त करती है कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव नई पीढ़ी में आजादी पाने के लिए दिए गए बलिदानों की स्मृति जगाते हुए संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ दायित्वों का बोध कराएगा तथा हम सबको एक गौरवशाली, समर्थ, समता और न्यायमूलक भारत के पुनर्निर्माण की प्रेरणा देगा।

❑❑❑

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

अखिल भारतीय साधारण सभा

आश्विन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2078, 18 अक्टूबर, दिल्ली

प्रस्ताव क्रमांक 3

शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण अविलंब किया जाए

शिक्षा एवं शिक्षकों की कई समस्याएँ शासन की उपेक्षा और अनिर्णय के कारण काफी समय से लंबित पड़ी है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह साधारण सभा सरकार से मांग करती है कि संवेदनशील रुख दिखाते हुए समस्याओं का समाधान अविलंब किया जाए।

1. संपूर्ण देश में सभी स्तरों पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर स्थाई और नियमित नियुक्ति सुनिश्चित की जाए तथा तदर्थवाद बंद किया जाए।
2. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जाए तथा इसकी विसंगतियों को दूर किया जाए।
3. 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना सभी शिक्षकों के लिए बहाल की जाए।
4. संपूर्ण देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जाए।
5. सभी स्तरों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुदृढ़ एवं नियमित व्यवस्था की जाए।
6. उच्च शिक्षा के शिक्षकों को समयबद्ध करियर एडवांसमेंट योजना का लाभ देना सुनिश्चित किया जाए।
7. सेवारत शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्स वर्क से मुक्त किया जाए अथवा कोर्स वर्क हेतु सवैतनिक अवकाश/ऑनलाइन व्यवस्था हो।
8. अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के भुगतान की कोषागार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
9. स्कूल एवं उच्च शिक्षा के समस्त शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए निशुल्क स्वास्थ्य कार्ड जारी कर प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
10. प्रोन्नति हेतु पूर्व सेवा काल को गणना में सम्मिलित किया जाए ।
11. पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक और अन्य समान सेवाओं की शिक्षकों के साथ समकक्षता स्थापित हो।
12. शिक्षकों से केवल शैक्षिक कार्य ही करवाए जाए। मिड-डे-मील योजना के प्रबंधन व क्रियान्वयन से शिक्षकों को मुक्त रखा जाए।
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जाए।
14. केंद्र सरकार अपने बजट का 10 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 30 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय सुनिश्चित करें ताकि पर्याप्त संख्या में शिक्षक एवं अन्य आधारभूत सुविधाएँ पुस्तकें, भवन, खेल के मैदान आदि उपलब्ध हो सके।
15. संपूर्ण देश में शिक्षा की स्वायत्तता को बहाल किया जाए। शिक्षा संबंधी सभी निर्णयों में शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद हो।
16. निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों को सुसंगत एवं व्यवहारिक बनाया जाए तथा उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएँ प्रदान की जाए।
17. प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाए।
18. शिक्षा के बाजारीकरण पर नियंत्रण सुनिश्चित हो।
19. एनसीईआरटी पूर्णतया शिक्षाविदों से युक्त स्वायत्त संस्था बने।
20. महाविद्यालय प्राचार्य का सेवाकाल 5 वर्ष तक ही सीमित न रखकर इसे सेवानिवृत्ति तक विस्तारित किया जाए।
21. सभी शिक्षण संस्थाओं में उचित शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में जितनी कक्षा उतने न्यूनतम शिक्षक तथा इससे ऊपर की शिक्षा देने वाले विद्यालयों में न्यूनतम प्रत्येक विषय में शिक्षक लगाए जाएँ। उच्च शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात के संबंध में यूजीसी के मानदंडों को लागू किया जाए।
22. कोरोना काल में दिवंगत हुए शिक्षकों के परिवार वालों को पर्याप्त एकमुश्त राशि देते हुए अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र की जाए।

❑❑❑

Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

Akhil Bharatiya Sadharan Sabha

Ashwin Shukla Trayodashi, Vikram Samvat 2078, 18 October, Delhi

Proposal No. 1

Collective efforts and adequate resources are necessary for the successful implementation of the National Education Policy.

The National Education Policy 2020 presents an unprecedented educational plan in the direction of building a capable, efficient, knowledgeable, self-reliant and confident Bharat. It is the unanimous opinion of the Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh that it is not just a general change made after 34 years in the education policy of India, but after 185 years it was able to free itself from the colonial mindset after the 'English Education Act' of 1835, and it is a proud document of making a self-respecting Bharat.

The General Assembly of Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh expresses satisfaction that extensive efforts have been made to create awareness regarding education policy at national, regional and state level with active participation of stakeholders, thereby creating a collective awareness in the educational community. The government has stepped ahead with several initiatives to implement this policy brought in last year on a practical level. The Samagra Shiksha Abhiyan has been revamped as per the provisions of the Education Policy and a clear, time bound roadmap SARTHAQ has been brought to achieve the goals and objectives of the National Education Policy.

NIPUN Bharat, NISHTHA 2.0, SAFAL, NETF, Vidya Pravesh, Bag Policy, Technical Education in Bhartiya Languages, Academic Bank of Credit and Multiple Entry & Exit, National Digital Education Architecture, Online Degree Programs, Standardization of Indian Sign Language, introduction of NCC as an Optional Subject, guidelines for internationalization of higher education, learning outcome based item bank, art integrated education, Manodarpan, DIKSHA, PARAKH, National Professional Standard for Teachers, National Mission for Mentoring, Blended Learning etc. are some of the major steps that will bring far-reaching impact and the above steps underscore the commitment and seriousness of the government for the implementation of education policy.

Welcoming the efforts of the Government, the General Assembly of the Akhil Bhartiya Rashtriya Mahasangh expresses its serious concern towards some of the processes of change and some of the ground problems. There are many serious challenges in implementing the above and the subsequent proposed changes in the education system uniformly upto the bottom. There is a huge shortage of teachers across the country, from pre-primary to higher education, lakhs of posts are lying vacant. Without trained professionals it is not possible to provide the required training related to various vocational subjects. A huge amount of resources are required to change the system in line with the National Education Policy, but no separate fund has been announced in the budget for this. There has been no positive government effort so far in relation to the proposed expenditure on education going up to 6% of GDP. The ABRSM opines that lack of adequate financial resources is a major obstacle in achieving the goals of education policy.

The circumstances of the Corona epidemic had to bring online or blended education into the education system, but it has exposed the digital divide and the geographical disparity of the digital infrastructure in the country. According to the recommendations of the Education Policy, to take any kind of technological innovation to the bottom, a large-scale infrastructure has to be created, which requires investment of huge amount of resources. The General Assembly of the Mahasangha opines that technology has limitations with its benefits, especially in teaching and learning. According to the National Policy on Education, the basis of learning lies in observing, listening, asking questions, experimenting etc. These are all practical experiences that require interest, motivation, engagement and an understanding of the purpose of the learning. The integration of technology in education should be done keeping this in view.

This general assembly of the Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh understands that due to the Corona epidemic, reverse migration, job loss, economic slowdown and the compulsion to study online have been very harmful for education. The dropout rate has increased significantly and the learning gaps have widened. As per the National Policy on Education, collective efforts are needed to bridge these gaps before the changes in the system can be brought down to the bottom.

The successful and holistic implementation of the National Education Policy is possible only with the joint efforts of the State and Central Governments. Many states like Karnataka, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana have made good progress in this direction, but still there is a state of indifference regarding this subject in some states.

In order to fully implement the education policy to the ground completely, all the parties need to work unitedly for the future of the country, leaving aside their personal and political interests. The ABRSM is of the view that teachers, students and all stakeholders need to transform themselves with a positive mindset about the changes taking place in the system. In order to make the implementation of the National Education Policy successful, this General Assembly calls upon the Central and State Governments, social institutions, experts, parents, teachers and members of the community to work unitedly at their respective levels and encourage the educational institutions, implementing agencies, students and Calls for establishing a symbiotic relationship between the key people of the industrial sector.

❑❑❑

Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

Akhil Bharatiya Sadharan Sabha

Ashwin Shukla Trayodashi, Vikram Samvat 2078, 18 October, Delhi

Proposal No. 2

Let the Amrit Mahotsav of Independence be a Festival of National Reconstruction

The Amrit Mahotsav of Independence is a sacred occasion for all of us to remember the dreams, hopes and aspirations that our ancestors cherished while fighting for freedom. The pride of a nation remains awake only when it constantly inspires, cultivates and endeavours to inculcate the traditions of its self-respect and sacrifice to the next generation. Bharat's freedom struggle is a sacred saga of long struggle, innumerable sacrifices and austerities, which culminated in the form of Independent Bharat 74 years ago. This festival is a declaration of preparation for the reconstruction of Bharat by embodying the collective dreams of 'We, the people of Bharat!' and preserving our cultural life on the basis of its glorious history.

India's young generation is the largest in the world today . It is a well thought opinion of the General Assembly of Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh that the Amrit Mahotsava of our independence should become a festival for every Indian's heart and soul, so that feeling proud of our roots, we may become able to see with our own body and our own eyes, the ever new and antiquated venerable India, that is capable to provide leadership to the world and face the challenges of the new century. The Amrit Mahotsav of Independence is an opportunity to create innovative programs with public participation in the light of the pious energy of the freedom struggles. Small and spatial local programs across the country can serve a larger national interest.

The Mahasangha believes that many incidents of freedom movement and contribution of freedom fighters either did not come before the country; or did not come in the form it was supposed to come. This general assembly calls upon all the teachers, educationists and the society in general to bring credible information about our freedom movement and undiscovered heroes to the country, so that all of us can get inspiration from these unknown or little published struggles which have carried the torch of freedom burning in every part of the country in every period.

Our saints, teachers and Acharyas also contributed in their own way to keep the flame of freedom burning across the country. During the freedom struggle, there has been a long series of efforts to awaken the conscience through education according to the national ideals and needs. We have also got this pious opportunity to think and discuss the educational system that the great men of our country had dreamed and lived for. Like the history of the freedom movement, the journey of 75 years of our independence has been a testimony to the dedication, enterprise and talent of us.

The General Assembly of the Mahasangh has a unanimous opinion that this festival should become a golden time to re-know India's progress and achievements in every field viz. our learning, our science, our economy etc and instead of being ashamed of the weaknesses left during this period, we should take a pledge to overcome the same.

In this auspicious time, Mahasangh calls upon its members and entire teaching community to prepare inspiring programs for the society at their respective places like, 'My Institute of Education - My Tirtha' and activities that promote patriotism, cultural heritage and the unity of India among students; Seminars and Lectures on topics such as Indian Freedom Struggle, Aftermath Journey and Our Responsibility may also be organised; Every person associated with us through innovative programs like Jagran Abhiyan for Swadeshi and Self-Reliant India should be a part of this Amrit Mahotsava, and our individual as well as collective efforts should contribute India reach to the ultimate glory. It is the humble expectation of the Mahasangh.

This general assembly of the Mahasangh expresses the belief that the Amrit Mahotsava of independence will awaken in the new generation the memory of the sacrifices made to win freedom, and make us aware of our duties along with the rights promised in the Constitution and we will all have a proud, capable, equality and justice based Indian nation. This Mahotsava will definitely inspire us for the reconstruction of Bharat.

❑❑❑

Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

Akhil Bharatiya Sadharan Sabha

Ashwin Shukla Trayodashi, Vikram Samvat 2078, 18 October, Delhi

Proposal No. 3

The problems of education and teachers should be resolved immediately.

Many problems of education and teachers have been pending for a long time due to the neglect and indecision of the government. This general body of the Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh demands from the government that the problems should be resolved without any delay by showing a sensitive attitude.

1. Permanent and regular appointment of teachers should be ensured at all levels all over the country and adhocism should be stopped.
2. The recommendations of the Seventh Pay Commission should be implemented uniformly throughout the country and its anomalies should be removed.
3. The pension scheme before 1 January 2004 should be restored for all teachers.
4. The retirement age of teachers should be uniformly 65 years across the country.
5. Systematic and regular arrangements should be made for the training of teachers at all levels.
6. Time bound benefits of career advancement scheme to the teachers of higher education should be ensured.
7. Serving teachers should be exempted from PhD course work or there should be paid leave / online arrangement for course work.
8. The treasury system for payment of aided educational institutions should be ensured.
9. The teachers of schools and higher education be provided free Health Care facility for their proper medical treatment and its proper implementation be ensured.
10. Past service should be included in the calculation for promotion.
11. Parity of librarians, physical teachers and such other equal services be maintained with the teachers.
12. Only educational work should be done by teachers. Teachers should be kept free from the management and implementation of the Mid Day Meal Scheme.
13. National Education Policy 2020 should be implemented uniformly across the country.
14. The Central Government and the State Governments should ensure that 10% and 30% of their budget respectively is spent on education so that adequate number of teachers and other basic facilities like books, buildings, playgrounds etc. can be made available.
15. The autonomy of education should be restored throughout the country. The participation of teachers should be ensured in all decisions related to education and political and administrative interference should be stopped.
16. The provisions of the Right to Free and Compulsory Education should be made consistent and practical and necessary resources and facilities should be provided to ensure their compliance.
17. Primary education should be given in mother tongue only.
18. Ensure control over the commercialization of education.
19. NCERT be made autonomous, fully managed by educationists.
20. The tenure of the college principal should not be limited to 5 years and should be extended till retirement.
21. Proper teacher student ratio should be ensured in all educational institutions. minimum one teacher for each class in primary schools and minimum one teacher for each subject in schools teaching above primary. UGC norms regarding teacher student ratio in higher education should be implemented.
22. Sufficient one time lump sum amount and compassionate appointment should be made at the earliest to the families of the teachers who died recently during corona pandemic.

❑ ❑ ❑